* ओड़िशा संस्करण

www.epaper.azadsipahi.com

10 सितंबर, 2022
भाद्रपद, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा
संवत 2079
पृष्ठ : 12, मूल्य : ₹3.00

रांची
शनिवार, वर्ष 07, अंक 321

कलम कलम बढ़ाये जा

# आजाद सिपाही

नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत : गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार, पिटिशनर से कहा- इसे वापस लो

# राज्यपाल निर्वाचन आयोग के पत्र को सार्वजनिक करें: झामुमो

## सुप्रियो ने कहा : अच्छा-बुरा, काला-उजला जो भी हो बतायें

आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** झारखड में सियासी हलचल जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम लोगों की नजर राजभवन पर टिकी हुई है। यूपीए इस मामले में जल्द पटाक्षेप चाहता है। इसी संदर्भ में झामुमो ने एक बार फिर राज्यपाल से मुख्यमंत्री के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य के लिए राज्यपाल चुप्पी तोड़ें। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यपाल राज्य में बरकरार भ्रम की स्थिति दूर करें।

**राज्यपाल ने एक-दो दिन का दिया था आश्वासन :** सुप्रियो ने कहा कि राज्यपाल रमेश बैस 6 दिन के लंबे दिल्ली प्रवास से लौटे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने अपने स्वास्थ्य का चेकअप भी कराया है। वह स्वस्थ रहें, इसकी भी कामना करता हूं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड का स्वास्थ्य भी लोकतांत्रिक तरीके से सुधरे, इसका भी प्रयास होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लेकर 01 सितंबर को राजभवन जाकर असमंजस दूर करने की गुहार लगायी थी। इस दौरान राज्यपाल ने उस समय दो दिन में अपने मंतव्य से निर्वाचन आयोग को अवगत कराने का भरोसा दिलाया था, परंतु दूसरे दिन दिल्ली चले गये।

**अच्छा-बुरा, काला-उजला जो हो, वह हो सार्वजनिक :** सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल के आश्वासन का आज सातवां दिन है। लेकिन अभी तक बातें स्पष्ट नहीं हो पायी हैं कि निर्वाचन आयोग के लिफाफे में क्या है। उन्होंने कहा कि हमने सदन में अपनी ताकत दिखा दी और विपक्ष वॉक आउट कर गया। लेकिन राज्यपाल रमेश बैस के चुनाव आयोग की सिफारिश और अपना मंतव्य न रखने से राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि अच्छा-बुरा, काला उजला जो भी निर्वाचन आयोग के पत्र में है, वह सार्वजनिक किया जाये।

### झामुमो के आरोप पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने साधा निशाना

**रांची (आजाद सिपाही)।** आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर झामुमो पर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि क्या किसी दल ने कहा था कि अपने हाथों से माइंस का लीज ले लीजिए। उन्होंने कहा कि बार-बार झामुमो की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्ष की भूमिका क्या है। खुद हेमंत ने खदान की लीज अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम ली है। श्री महतो ने कहा कि जिस कठघरे में आप खुद खड़े हैं, इसे किसी दूसरे पर थोपने से तो नहीं चलेगा। विपक्ष पर आरोप मढ़ कर अपने समर्थकों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इन झूठे तर्कों से राज्य नहीं चलेगा। कौन सच्चा कौन झूठा है इसके लिए विधान बना हुआ है, संविधान बना हुआ है। इसके दायरे में ही सभी को रहना है। और इसी से राज्य चलता है। श्री महतो ने कहा कि झामुमो ने चुनाव के समय बहुत सारी घोषणाएं की थीं, मगर क्या हुआ। उन्होंने सदन में सरकार के वादों को भी गिनाया। सुदेश महतो ने कहा कि महिला आयोग खाली है, जेपीएससी के चेयरमैन नहीं हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि हर रिक्ति पर पचास फीसदी महिलाओं का आरक्षण होगा, क्या हुआ। 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण झामुमो के चुनावी घोषणा पत्र में था। चुनाव में लोक लुभावन वादा करके सत्ता में आ गयी, लेकिन अब अपने वादे भूल गयी।

# पति की कब्र के बगल में दफनायी जायेंगी क्वीन

## ब्रिटेन में 12 और भारत में एक दिन शोक

एजेंसी

**लंदन।** ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। उन्होंने 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन का शासन संभाला था। 8 सितंबर को उनके निधन के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक, 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जायेगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है।



स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जायेगा। यहां वेस्टमिंस्टर ऐबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जायेगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराओं के तहत दिवंगत महारानी को शुक्रवार को शाही गन सैल्यूट दिया गया। क्वीन 96 साल की थीं, इसलिए उन्हें हर साल के हिसाब से 96 राउंड की फायरिंग के साथ गन सैल्यूट दिया गया। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल से लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जायेगा। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल रहेंगे।

## भाजपा ने जारी की 14 राज्यों के प्रभारियों की सूची

### सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड प्रभारी

आजाद सिपाही संवाददाता

**नयी दिल्ली।** भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की। विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी को बिहार, ओम माथुर और नितिन नवीन को छत्तीसगढ़, विप्लव कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, पी मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे और राम शंकर कठेरिया को मध्यप्रदेश, विजय रूपाणी और नरिंदर सिंह रैना पंजाब, विजय रूपाणी को चंडीगढ़, अरुण सिंह और विजया रहाटकर को राजस्थान का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संबित पात्रा और ऋतुराज सिन्हा को नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों का कोआर्डिनेटर और जॉइंट कोआर्डिनेटर बनाया गया है।

# संजय कुमार मिश्र, जिन्होंने इडी को दी नयी ताकत

**आखिर कौन हैं संजय कुमार मिश्रा? जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी की नहीं सुनी। जिनके लिए सरकार ने एक्ट में बदलाव किया। जिसने अकेले ही भारत में वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके काम के तरीके के कायल हैं। संजय कुमार मिश्रा और इडी के संबध पर 'आजाद सिपाही' की खास रिपोर्ट।**

आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के निदेशक हैं। वह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। संजय कुमार मिश्रा 1984 में आइआरएस में चयनित हुए थे। उस समय के सबसे कम उम्र के आइआरएस अधिकारी थे। उन्होंने अपना अधिकांश करियर आयकर विभाग में बिताया। वह अपने तेज दिमाग, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए मशहूर थे। संजय कुमार मिश्रा जानते थे कि भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा भारत विरोधी ताकतों, विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों, भ्रष्ट भारतीय राजनेताओं और उनका ईंधन काला धन है। वे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनजीओ, कॉरपोरेट्स, शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भ्रष्ट भारत के विकास को रोकने के लिए नये भारत के निर्माण पर काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के पहले 2-3 साल याद हैं, तो एनजीओ, शेल कंपनियों पर भारी कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सांठगांठ बहुत बड़ी है। उन्हें इन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए समान रूप से सक्षम टीम बनानी होगी। तभी संजय कुमार मिश्रा आते हैं। मोदी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने संजय कुमार मिश्रा को अपना दृष्टिकोण बताया और उन्हें 2018 में इडी का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्हें पहली बार इडी के प्रधान सचिव और 19 नवंबर, 2018 को इडी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय इडी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करता है।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। यह विदेशी निर्देश पर स्थानीय रूप से पैसे का आदान-प्रदान करने के लिए एक सरल शब्द है। जैसे मैं भारत में एक दोस्त से आपको 100 रुपये देने के लिए कहता हूं और बदले में मैं यूएस में दोस्त रिश्तेदार को 1 डॉलर का भुगतान करता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को वैध धन बनाने का एक रास्ता भी है।

**मोदी का पुरानी वीडियो बहुत कुछ कह रहा :** मैं मोदी का पुराना वीडियो सर्च कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'जितने भी लोगों को भरती करना पड़े, मैं करूंगा, पर 70 सालों में जितना भी देश को लूटा, मैं सबका पता लगा लूंगा।' एसके मिश्रा ने इडी का निर्माण शुरू किया। उनसे पहले मुश्किल से 23 वरिष्ठ अधिकारी थे, अब 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी हैं। इडी के कार्यालय पूरे भारत में हैं। इडी के पास असीमित शक्ति है। वे कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इन शक्तियों का उपयोग करके एसके मिश्रा ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू की।

### मोदी अप्रत्याशित हैं

किसी ने यह नहीं सोचा था कि सरकार भ्रष्टाचार पर इस तरह की कार्रवाई करेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार भारत में सामान्य मानदंड बन गया था। इडी ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, चंद्र कोचर समेत कई नेता इडी के रडार पर आ गये। एस के मिश्रा की सेवानिवृत्ति मार्च 2020 को होनी थी। **(शेष पेज 10 पर)**

# हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नये चेयरमैन

आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** झारखंड हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अमिताभ कुमार गुप्ता झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नये अध्यक्ष होंगे। इनकी नियुक्ति को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकी नियुक्ति अगले पांच वर्ष तक के लिए की गयी है।

पिछले वर्ष जून से निवर्तमान चेयरमैन अरविंद प्रसाद के इस्तीफे के बाद से यह पद रिक्त था। अब आयोग फुल बेंच में आ गया। इससे पूर्व सरकार ने आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति की थी। पिछले वर्ष फरवरी से ही आयोग पूरी तरह से डिफंक्ट था। अब चेयरमैन की नियुक्ति के बाद आयोग का कोरम पूरा हो गया।